

2) राज्यपाल (Governor)

● महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

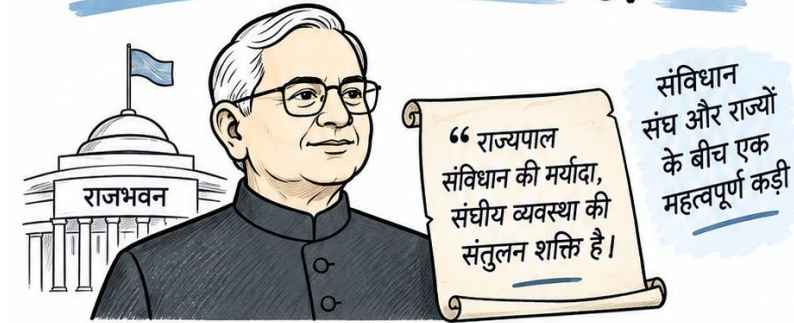
● राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां

● विवेकाधीन शक्तियां (Discretionary Powers)

● विवाद के प्रमुख बिंदु (Friction Areas)

● सुधार हेतु प्रमुख आयोग और उनकी सिफारिशें

राज्यपाल – दोहरी भूमिका



1 दोहरी भूमिका

- राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख
- संवैधानिक / नाममात्र प्रमुख
- केंद्र सरकार का प्रतिनिधि
- इसी कारण राज्यपाल की दोहरी भूमिका मानी जाती है।



संविधान की भावना के अनुरूप कार्य

2 महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य स्तर पर उप-राज्यपाल (Lieutenant Governor) का कोई पद नहीं होता।
- उपराज्यपाल / LG का पद केवल केंद्रशासित प्रदेशों में होता है।



एक नज़र में अंतर



राज्य

→
राज्यपाल



केंद्रशासित प्रदेश

→
उपराज्यपाल (LG)

2) Governor

Important Constitutional Provisions

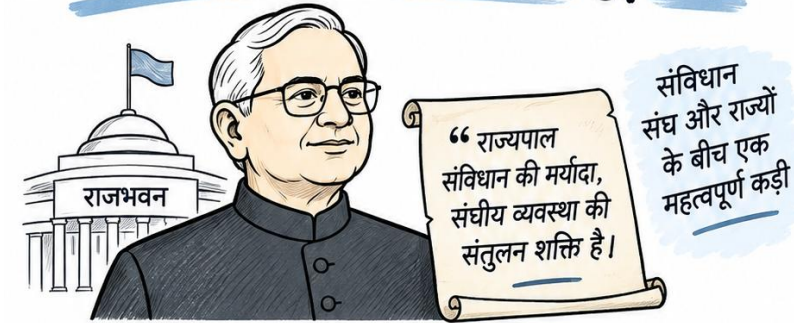
Key powers of the Governor

Discretionary powers

Key points of controversy

Major commissions for reform and their recommendations

राज्यपाल – दोहरी भूमिका



1 दोहरी भूमिका

- राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख
- संवैधानिक / नाममात्र प्रमुख
- केंद्र सरकार का प्रतिनिधि
- इसी कारण राज्यपाल की दोहरी भूमिका मानी जाती है।



2 महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य स्तर पर उप-राज्यपाल (Lieutenant Governor) का कोई पद नहीं होता।
- उपराज्यपाल / LG का पद केवल केंद्रशासित प्रदेशों में होता है।



एक नज़र में अंतर



राज्य

→
राज्यपाल



केंद्रशासित प्रदेश

→
उपराज्यपाल (LG)

❑ राज्यपाल का पद (अनुच्छेद 153)

- प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
- 7वाँ संविधान संशोधन, 1956 — एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

❑ राज्य की कार्यपालिका शक्ति (अनुच्छेद 154)

- राज्य की कार्यपालिका शक्ति → राज्यपाल
- वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

❑ राज्यपाल की नियुक्ति (अनुच्छेद 155)

- नियुक्ति → राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant)
 - ✓ केंद्र द्वारा मनोनीत
 - ✓ अमेरिकी मॉडल (निर्वाचित) को छोड़कर कनाडाई मॉडल (नियुक्त)
 - ✓ पहली महिला राज्यपाल : सरोजिनी नायडू (संयुक्त प्रांत, 1947)
 - ✓ हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक (1979) : राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है; यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है।
- "प्रत्यक्ष निर्वाचन" के स्थान पर "नियुक्ति" क्यों?
 - ✓ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव (दोनों जनादेश का दावा करते)
 - ✓ राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है
 - ✓ राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह व्यक्तिगत मामला बन जाता
 - ✓ निर्वाचन से अलगाववादी प्रवृत्ति को बल मिलता
 - ✓ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति से केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण बना रहता है।
 - ✓ राज्यपाल का चुनाव आम चुनाव के समय होने पर गंभीर समस्या खड़ी होती।

❑ Office of Governor - Article 153)

- There shall be a Governor for each State
- **7th Constitutional Amendment, 1956** - the same person can be appointed as Governor of two or more States

❑ Executive Power of the State - Article 154)

- Executive power of the State → vested in the Governor
- He shall exercise this power either directly or through officers subordinate to him, in accordance with the Constitution

❑ Appointment of Governor - Article 155)

- Appointment → by the President, by warrant under his hand and seal
 - ✓ Nominated by the Centre
 - ✓ The Canadian model (appointed) was adopted instead of the American model (elected)
 - ✓ First woman Governor: Sarojini Naidu (United Provinces, 1947)
 - ✓ Hargovind Pant v. Raghukul Tilak (1979): The office of Governor is not employment under the Central Government; it is an independent constitutional office.
- Why "appointment" instead of "direct election"?
 - ✓ Conflict between Governor and Chief Minister (both would claim a mandate)
 - ✓ The Governor is only a constitutional head
 - ✓ Election of the Governor would become a purely personal affair
 - ✓ Election would strengthen separatist tendencies
 - ✓ Appointment by the President maintains the Centre's control over the States.
 - ✓ Election of the Governor coinciding with general elections would create a serious problem.

□ राज्यपाल का कार्यकाल और इस्तीफ़ा (अनुच्छेद 156)

- अनुच्छेद 156(1) → राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
 - ✓ राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है,
 - ✓ एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण
 - ✓ पुनर्नियुक्ति कर सकता
 - ✓ संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया या आधार (Grounds) का कोई उल्लेख नहीं है।
 - ✓ सूर्य नारायण चौधरी बनाम भारत संघ (1981) द्वारा पुष्टि
- अनुच्छेद 156(2) → राष्ट्रपति को त्याग पत्र
- अनुच्छेद 156(3) → उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन रहते हुए, 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
 - ✓ कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद, राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।

बी.पी.सिंघल बनाम भारत संघ (2010)

- 'प्रसादपर्यंत' का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति मनमाने या अनुचित तरीके से राज्यपाल को पद से हटा दे।
- केवल केंद्र में सरकार बदलने के आधार पर राज्यों के राज्यपालों को एकमुश्त हटा देना असंवैधानिक है।
- राज्यपाल केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी या एजेंट नहीं है।
- यदि याचिकाकर्ता यह सिद्ध कर दे कि हटाने का निर्णय दुर्भावनापूर्ण (malafide) या मनमाना था, तो न्यायालय इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

❑ Term and Resignation of Governor - Article 156

- **Article 156(1) → holds office during the pleasure of the President**
 - ✓ The President can remove the Governor at any time
 - ✓ Transfer from one State to another
 - ✓ Can reappoint
 - ✓ The Constitution mentions no procedure or grounds for removing the Governor
 - ✓ Confirmed by *Surya Narain Choudhary v. Union of India* (1981)
- **Article 156(2) → resignation submitted to the President**
- **Article 156(3) → subject to the above provisions, shall hold office for a term of 5 years**
 - ✓ Even after the term ends, the Governor continues in office until his successor takes charge

B.P. Singhal v. Union of India (2010)

- ("Pleasure" does not at all mean that the President can remove the Governor arbitrarily or improperly.)
- Removing all State Governors en masse merely because the government at the Centre has changed is unconstitutional.
- The Governor is not an employee or agent of the Central Government.
- If the petitioner proves that the removal decision was malafide or arbitrary, the court can judicially review that decision.

राज्यपाल की योग्यताएं (अनुच्छेद 157)

- भारत का नागरिक हो
- न्यूनतम आयु → 35 वर्ष
- दो परंपराएँ (संविधान में नहीं)
 - ✓ राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ वह नियुक्त किया जाता है — ताकि स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
 - ✓ राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति (केंद्र) संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे — ताकि संवैधानिक व्यवस्था सुचारु चले।
- इन दोनों परंपराओं का कई मामलों में उल्लंघन हुआ है।



सरकारिया आयोग (1983-88) की सिफारिशें

राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति

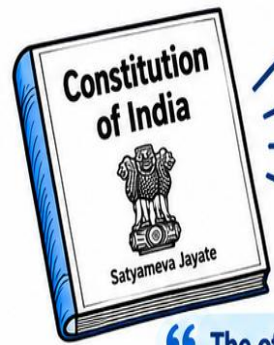


“राज्यपाल पद का राजनीतिकरण नहीं, बल्कि संवैधानिक गरिमा और तटस्थता”

- 1** वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित (Eminent) व्यक्ति हो।
- 2** वह संबंधित राज्य के बाहर का व्यक्ति हो।
- 3** वह एक तटस्थ व्यक्ति हो, जिसका राज्य की स्थानीय राजनीति से गहरा संबंध न हो।
- 4** वह ऐसा व्यक्ति हो जिसने हाल के समय में राजनीति में बहुत अधिक भाग न लिया हो।
- 5** केंद्र में सत्तारूढ़ दल के किसी राजनेता को विपक्षी दल-शासित राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए।
- 6** नियुक्ति में मुख्यमंत्री से प्रभावी परामर्श हो; सुझाव — उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष से भी परामर्श हो।
- 7** राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल सामान्यतः बाधित न हो (दुर्लभ व बाध्यकारी कारणों को छोड़कर)।
- 8** राज्यपाल को पद छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति या लाभ के पद पर नहीं लौटना चाहिए (सिवाय उपराष्ट्रपति/राष्ट्रपति पद के)।

❑ Qualifications of Governor - Article 157

- Must be a citizen of India
- Minimum age → 35 years
- Two conventions (not in the Constitution)
 - ✓ The Governor should not be a resident of the State to which he is appointed — so as to remain free of local politics
 - ✓ Before appointing a Governor, the President (Centre) should consult the Chief Minister of the concerned State — so that constitutional machinery runs smoothly
- Both these conventions have been violated in several cases.



Sarkaria Commission (1983-88) Recommendations

Person to be Appointed as Governor

“ The office of Governor should reflect constitutional dignity and neutrality, not politicization. ”

Stronger Centre-State Relations, Stronger India

1 He/She should be an eminent person in some field of life. 	2 He/She should be from outside the concerned state. 
3 He/She should be a neutral person, with no deep connection to the local politics of the state. 	4 He/She should not have taken too active a part in politics in recent years. 
5 A politician from the ruling party at the Centre should not be appointed Governor of a state governed by an opposition party. 	6 The Chief Minister should be effectively consulted in the appointment; it was also suggested that the Vice-President and the Speaker of the Lok Sabha should be consulted. 
7 The Governor's five-year tenure should normally not be disturbed, except in rare and compelling circumstances. 	8 After demitting office, the Governor should not return to active politics or accept an office of profit, except the office of Vice-President or President. 

Strong Centre-State Relations, Strong Democracy

□ पद की शर्तें (अनुच्छेद 158)

- 158(1) → राज्यपाल संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
यदि कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है, तो पद ग्रहण की तिथि से उसका सदन का स्थान रिक्त माना जाएगा।
- 158(2) → वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
- 158(3) → बिना किराए के आधिकारिक निवास
 - ✓ वेतन → संसद द्वारा
 - ✓ राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982
 - ✓ राज्य की संचित निधि पर भारित
 - ✓ वित्त अधिनियम, 2018 → ₹3.50 लाख प्रतिमाह

- 158(3A) → यदि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो, तो वेतन-भत्ते उन राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में बाँटे जाएँगे।
- 158(4) → कार्यकाल के दौरान वेतन में कमी नहीं

उन्मुक्तियाँ एवं विशेषाधिकार (अनुच्छेद 361)

- ❖ राष्ट्रपति या राज्यपाल → कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं
- ❖ कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही न शुरू की जा सकती है, न जारी रखी जा सकती है (व्यक्तिगत कृत्यों के लिए भी)
- ❖ कार्यकाल के दौरान उसे गिरफ्तार या कारावास नहीं
- ❖ व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में दीवानी कार्यवाही शुरू की जा सकती है — परंतु उसे 2 माह पूर्व लिखित नोटिस

❑ Conditions of Office - Article 158)

- 158(1) → The Governor shall not be a member of either House of Parliament or a House of the State Legislature. If a member is appointed Governor, his seat is deemed vacant from the date he takes office.
- 158(2) → He shall not hold any other office of profit.
- 158(3) → Entitled to an official residence without payment of rent
 - ✓ Salary → determined by Parliament)
 - ✓ Governors (Allowances and Privileges) Act, 1982
 - ✓ Charged on the Consolidated Fund of the State
 - ✓ Finance Act, 2018 → ₹3.50 lakh per month

- 158(3A) → If the same person is Governor of two or more States, the salary/allowances shall be shared among those States in a proportion determined by the President
- 158(4) → No reduction in salary during the term of office

Immunities and Privileges - Article 361

- ❖ President or Governor → not personally answerable to any court for the exercise/performance of their duties
- ❖ No criminal proceedings can be instituted or continued against him in any court during his term (even for personal acts)
- ❖ No arrest or imprisonment during the term
- ❖ Civil proceedings regarding personal acts can be initiated — but only after 2 months' prior written notice

❑ शपथ (अनुच्छेद 159)

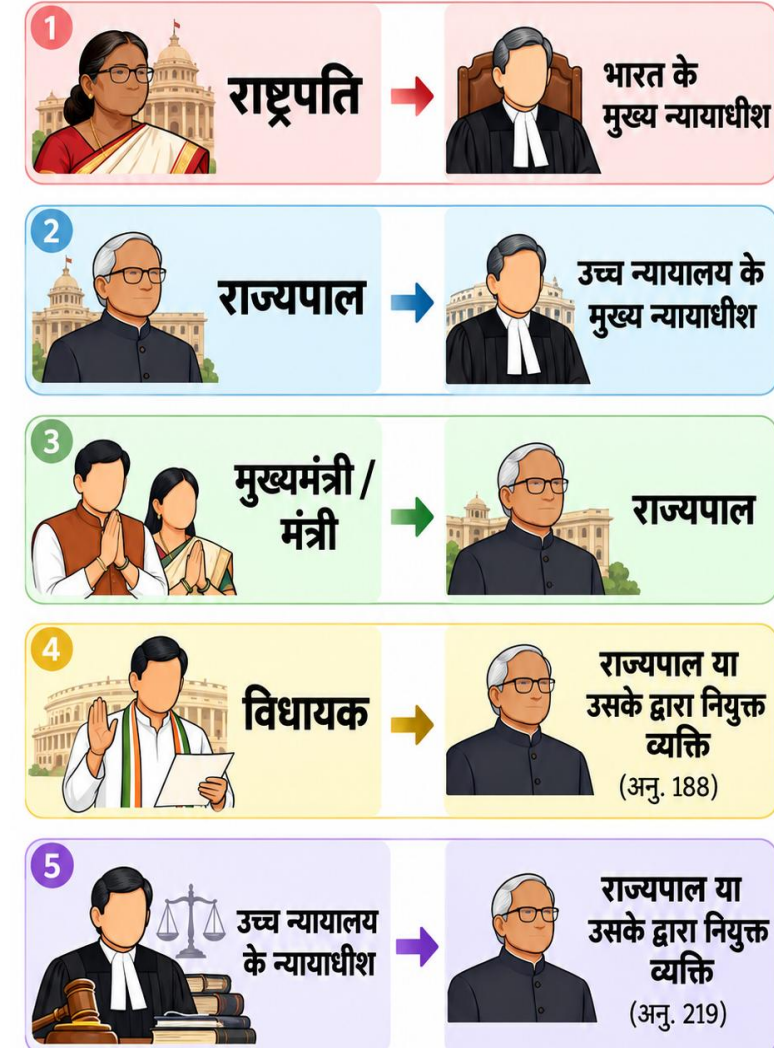
- ❑ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश;
- ❑ उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय का वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश।
- ❑ शपथ के तत्व:
 - 1) निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन;
 - 2) अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण
 - 3) स्वयं को राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित करना।

❑ कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन (अनुच्छेद 160)

- ❑ यदि कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका उल्लेख संविधान के इस अध्याय में नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति (President) राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है जो वह उचित समझे।
- ❑ परम्परा → जब अनुच्छेद 160 के तहत ऐसी स्थिति आती है, तो राष्ट्रपति आमतौर पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।



महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के लिए शपथ दिलाने वाला प्राधिकारी

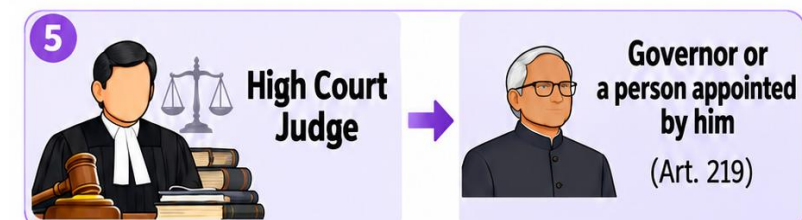
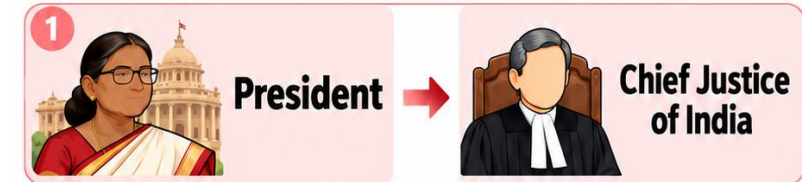


❑ Oath — Article 159

- ❑ Administered by the Chief Justice of the concerned State's High Court
- ❑ In his absence, the senior-most available judge of that court
- ❑ Elements of the oath :
 - 1) Faithful discharge of duties
 - 2) To the best of his ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law
 - 3) Devote himself to the service and well-being of the people of the State.

❑ Discharge of Governor's functions in certain contingencies — Article 160)

- ❑ If a contingency arises which is not provided for in this chapter of the Constitution, the President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the Governor's functions in the State.
- ❑ Convention → When such a situation arises under Article 160, the President usually appoints the Chief Justice of the concerned State's High Court, or in his absence the senior-most judge, to act as Governor.



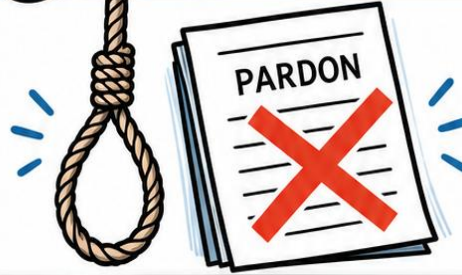
❑ राज्यपाल की "क्षमादान शक्ति" (अनुच्छेद 161)

- ❑ राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों (राज्य सूची और समवर्ती सूची) के तहत।
 - 1) क्षमा — दंड व दोषसिद्धि दोनों से पूर्ण मुक्ति।
 - 2) लघुकरण — दंड का हल्के प्रकार में परिवर्तन
 - 3) परिहार — दंड की प्रकृति बदले बिना अवधि घटाना
 - 4) विराम — विशेष परिस्थिति के कारण कम दंड।
 - 5) प्रविलंबन — दंड के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक।
- ❑ यह शक्ति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर प्रयोग होती है
- ❑ एपुरु सुधाकर केस (2006) : क्षमादान निर्णय की सीमित न्यायिक समीक्षा।

राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

अनुच्छेद 161

1 मृत्युदंड पर सीमा



राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः माफ (Pardon) नहीं कर सकता।

2 क्या कर सकता है?



राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन (Suspend), परिहार (Remit) या लघुकरण (Commute) कर सकता है।

3 सैन्य अदालत के संबंध में



राज्यपाल के पास सैन्य अदालत (Court Martial) द्वारा दी गई किसी भी सजा के संबंध में कोई शक्ति नहीं है।

❑ Governor's "Pardoning Power" - Article 161)

- ❑ In respect of matters to which the executive power of the State extends (State List and Concurrent List
 - 1) Pardon — complete relief from both sentence and conviction
 - 2) Commutation — changing the sentence to a lighter form
 - 3) Remission — reducing the period of sentence without changing its nature.
 - 4) Respite — awarding a lesser sentence due to a special circumstance
 - 5) Reprieve — a temporary stay on the execution of the sentence
- ❑ This power is exercised on the advice of the Council of Ministers
- ❑ Epuru Sudhakar case (2006): Limited judicial review of pardoning decisions

Governor's Clemency Power

Article 161

1 Limit on Death Sentence



The Governor cannot completely pardon a death sentence.

2 What can the Governor do?



The Governor can suspend, remit, or commute a death sentence.

3 Regarding Court Martial



The Governor has no power in respect of any sentence awarded by a Court Martial.



Remember: The Governor's power is exercised under Article 161.

❑ राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार (अनुच्छेद 162)

- ❑ राज्य सरकार केवल उन्हीं विषयों पर शासन चला सकती है, जो राज्य सूची में शामिल हैं (जैसे - पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन)
- ❑ यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य की शक्ति संघ (केंद्र) की कार्यपालिका शक्ति के अधीन रहेगी।

❑ मंत्रिपरिषद् (अनुच्छेद 163)

- ❑ 163(1) → जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से विवेक से कार्य करने की अपेक्षा है, उन्हें छोड़कर राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
 - ✓ शमशेर सिंह केस (1974): विवेकाधीन क्षेत्रों को छोड़कर राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही कार्य करेगा; वह व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करेगा, न ही सलाह के विरुद्ध जाएगा।
- ❑ 163(2) → कोई विषय विवेक का है या नहीं — इस पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम।
- ❑ 163(3) → मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या नहीं, और दी तो क्या — इसकी किसी न्यायालय में जाँच नहीं होगी।

❑ **Extent of Executive Power of the State - Article 162)**

- ❑ The State Government can govern only on matters included in the State List (e.g., police, agriculture, local government)
- ❑ On a Concurrent List subject, the State's power remains subject to the executive power of the Union (Centre)

❑ **Council of Ministers - Article 163**

- ❑ 163(1) → Except in matters where the Constitution requires the Governor to act in his discretion, there shall be a Council of Ministers, headed by the Chief Minister, to aid and advise the Governor
 - ✓ Shamsher Singh case (1974): Except in discretionary areas, the Governor shall act only on the advice of the Council of Ministers; he shall do nothing personally, nor act against that advice
- ❑ 163(2) → The Governor's decision on whether a matter falls within his discretion is final
- ❑ 163(3) → No court shall inquire into whether any advice, and if so what advice, was given by the Ministers to the Governor

❑ मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध (अनुच्छेद 164)

- ❑ 164(1) → मुख्यमंत्री (Chief Minister) की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
 - ✓ मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं
 - ✓ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में एक "जनजातीय कल्याण मंत्री"
 - ✓ 94वें संविधान संशोधन 2006 → 'बिहार' को हटा दिया गया और 'छत्तीसगढ़ व झारखंड' को जोड़ा गया था
- ❑ 164(1A) → 91वां संशोधन 2003 → CM सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं; **परंतु न्यूनतम 12**

- ❑ 164(1B) → 91वां संशोधन 2003 → दल-बदल के आधार पर निरर्ह घोषित विधायक मंत्री भी नहीं बन सकता
 - ✓ निरर्हता की अवधि → कार्यकाल समाप्ति या पुनः निर्वाचन तक
- ❑ 164(2) → मंत्रिपरिषद् विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी।
- ❑ 164(3) → पद ग्रहण से पहले राज्यपाल पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा (तीसरी अनुसूची)।
- ❑ 164(4) → 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।
- ❑ 164(5) → मंत्रियों के वेतन-भत्ते → राज्य विधानमंडल

❑ Other Provisions Relating to Ministers - Article 164

- ❑ 164(1) → The Chief Minister is appointed by the Governor. Other ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister.
 - ✓ Ministers hold office during the pleasure of the Governor
 - ✓ A "Minister of Tribal Welfare" in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha
 - ✓ 94th Constitutional Amendment, 2006 → 'Bihar' was removed and 'Chhattisgarh and Jharkhand' were added
- ❑ 164(1A) → 91st Amendment, 2003 → Total number of ministers including the CM shall not exceed 15% of the total membership of the Legislative Assembly, subject to a minimum of 12

- ❑ 164(1B) → 91st Amendment, 2003 → A legislator disqualified on grounds of defection also cannot become a minister
 - ✓ Period of disqualification → until the end of the term or re-election
- ❑ 164(2) → The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly
- ❑ 164(3) → Before taking office, the Governor administers the oaths of office and secrecy (Third Schedule).
- ❑ 164(4) → Must become a member of either House of the Legislature within 6 months, otherwise must vacate the office of minister.)
- ❑ 164(5) → Salaries and allowances of ministers → determined by the State Legislature

□ महाधिवक्ता (Advocate General) : अनुच्छेद 165

- राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी
- 165(1) → राज्यपाल (Governor) द्वारा नियुक्ति
 - ✓ योग्यता : उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो → अनु. 217(2)
- 165(2) → कार्य और कर्तव्य
 - ✓ राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल सौंपे;
 - ✓ विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन जो राज्यपाल सौंपे;
- 165(3) → कार्यकाल और पारिश्रमिक → राज्यपाल के प्रसादपर्यंत
- हटाने की कोई प्रक्रिया/आधार संविधान में नहीं।



1 अधिकार

1 अनु. 177: विधानमंडल के दोनों सदनों (व उनकी समितियों, जिनका वह सदस्य नामित हो) की कार्यवाही में बोलने व भाग लेने का अधिकार — परंतु मत देने का अधिकार नहीं।



2 अनु. 194(4): विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार व उन्मुक्तियाँ।

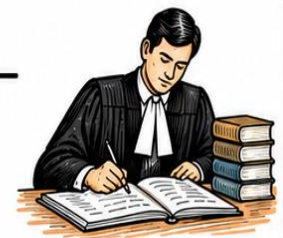


3 राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार।



2 स्थिति

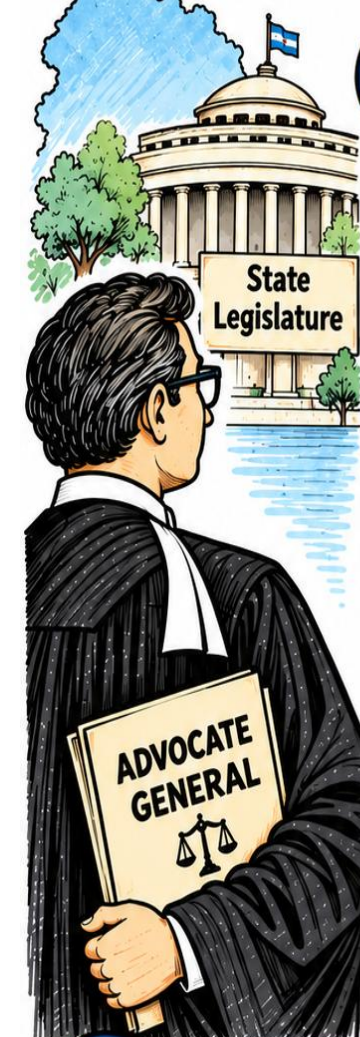
- वह पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं — निजी वकालत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं (राज्य के विरुद्ध नहीं)।



राज्य के विरुद्ध नहीं

❑ Advocate General - Article 165

- ❑ The State's highest law officer
- ❑ 165(1) → Appointed by the Governor
 - ✓ Qualification : must be qualified to be appointed a Judge of a High Court → Art. 217(2)
- ❑ 165(2) → Functions and duties
 - ✓ To advise the State Government on legal matters referred to him by the Governor
 - ✓ To perform other duties of a legal character assigned by the Governor
- ❑ 165(3) → Term and remuneration → during the pleasure of the Governor
- ❑ No procedure/grounds for removal specified in the Constitution.



1 Rights

1 Article 177:

The right to **speak and participate** in the proceedings of both Houses of the State Legislature (and their committees, of which he is nominated as a member) — but **no right to vote**.



2 Article 194(4):

All the **privileges and immunities** enjoyed by the members of the State Legislature.



3 The right to be heard

in any court of the State.



2 Position

- He is **not a full-time government employee** — there is no absolute bar on private legal practice (**except against the State**).



No practice against the State

❑ राज्य सरकार के कार्यों का संचालन : अनुच्छेद 166

- ❑ 166(1) → राज्य सरकार की समस्त कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से।
- ❑ 166(2) → राज्यपाल के नाम से बनाए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को उस तरीके से प्रमाणित किया जाएगा, जो राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट हो।
- ❑ 166(3) → राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक ढंग से पूरा करने के लिए नियम बनाएगा।
 - ✓ वह मंत्रियों के बीच कार्यों के बंटवारे (पोर्टफोलियो/विभाग आवंटन) के लिए भी नियम बनाएगा।

❑ मुख्यमंत्री के कर्तव्य : अनुच्छेद 167

- ❑ 167(a) → राज्य के प्रशासन और कानून बनाने (विधायी) के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना।
- ❑ 167(b) → राज्य के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी राज्यपाल को सौंपना, जो राज्यपाल द्वारा मांगी जाए।
- ❑ 167(c) → यदि राज्यपाल अपेक्षा करे (चाहे), तो किसी ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद् के सामूहिक विचार के लिए प्रस्तुत करना, जिस पर किसी एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले लिया है, लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद् ने उस पर विचार नहीं किया है।

❑ Conduct of Business of the Government of a State -

Article 166

- ❑ 166(1) → All executive action of the State Government is taken in the name of the Governor
- ❑ 166(2) → Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated in the manner specified in rules made by the Governor.
- ❑ 166(3) → The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the State Government
 - ✓ He shall also make rules for the allocation of business (portfolios/departments) among ministers

❑ Duties of Chief Minister - Article 167

- ❑ 167(a) → To communicate to the Governor all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of State affairs and proposals for legislation
- ❑ 167(b) → To furnish such information relating to the administration of State affairs and legislative proposals as the Governor may call for.
- ❑ 167(c) → If the Governor so requires, to submit for consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister individually but which has not been considered by the Council

प्रथम प्रशासनिक सुधार — 1966	राजमन्नार समिति — 1969	सरकारिया आयोग — जून 1983
○ प्रथम अध्यक्ष → मोरारजी देसाई, — बाद में के. हनुमंतैया ○ रिपोर्ट : 1966 से 1970 के बीच द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005, वीरप्पा मोइली — बाद में वी. रामचंद्रन)	○ तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में गठित → रिपोर्ट — 1971 ○ अध्यक्ष — डॉ. पी.वी. राजमन्नार (मद्रास HC) ○ केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बनी पहली बड़ी समिति	○ अध्यक्ष → रणजीत सिंह सरकारिया (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) → रिपोर्ट — 1988 ○ केंद्र-राज्य संबंधों पर सबसे प्रामाणिक और सर्वाधिक उद्धृत आयोग ○ राज्यपाल को हटाने का कारण बताना चाहिए और हटाने से पूर्व उसे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।
○ किसी भी व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया। ○ नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श अवश्य। ○ सार्वजनिक व प्रशासनिक अनुभवयुक्त व्यक्ति।	○ राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से ही होनी चाहिए। ○ एक समिति गठित की जानी चाहिए जिसके सदस्य — न्यायाधीश, प्रख्यात वकील व प्रशासक हों।	○ राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ○ अनुच्छेद 156 में संशोधन कर, नियुक्ति में मुख्यमंत्री की प्रभावी सलाह-मशविरा से निर्णय होना चाहिए। ○ राज्यपाल सक्रिय राजनीति से संबंधित न हो। ○ राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष निश्चित होनी चाहिए। ○ केंद्र में सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति राज्यपाल न हो और वह राज्य की राजनीति से आत्मीयता से न जुड़ा हो।

First Administrative Reforms Commission — 1966	Rajamannar Committee — 1969	Sarkaria Commission — June 1983
○ First Chairman → Morarji Desai, later K. Hanumanthaiya ○ Report: Second Administrative Reforms Commission functioned between 1966 and 1970 (2005, Veerappa Moily — later V. Ramachandran)	○ Constituted by the Tamil Nadu Government in 1969 → Report — 1971 ○ Chairman — Dr. P.V. Rajamannar (Madras HC) ○ First major committee formed to review Centre-State relations	○ Chairman → Ranjit Singh Sarkaria (Judge of the Supreme Court) → Report — 1988 ○ Most authoritative and most-cited commission on Centre-State relations ○ Reasons must be given for removing a Governor, and he must be given an opportunity to be heard before removal.
○ No person should be appointed Governor more than once. ○ Must consult the Chief Minister before appointment. ○ Should be a person with public and administrative experience.	○ The Governor should be appointed only in consultation with the Chief Minister. ○ A committee should be constituted, comprising members — a judge, an eminent lawyer, and an administrator.	○ The Governor should be an outsider to the State. ○ Article 156 should be amended so that appointment is decided after effective consultation with the Chief Minister. ○ The Governor should have no connection with active politics. ○ The Governor's term should be a fixed 5 years. ○ A person belonging to the ruling party at the Centre should not be made Governor, and he should have no close ties with the State's politics.

वेंकटचलैया आयोग — 2000

- **राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC)**
- न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)
- इसने मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन, शिक्षा के अधिकार, दल-बदल कानून में कठोरता, अंतर्राज्यीय परिषद को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जैसे विषयों पर भी सिफारिशें दीं।

- नियुक्ति हेतु समिति → केंद्र (प्रधानमंत्री, गृहमंत्री), राज्य (मुख्यमंत्री) और विधायिका (लोकसभा अध्यक्ष)
- कार्यकाल 5 वर्ष हो।
- हटाने से पहले मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए
- दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप न हो।
- विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमपूर्ण तरीके से हो
- राज्यपाल मित्र, दार्शनिक व मार्गदर्शक (friend, philosopher & guide) के रूप में कार्य करे।

पूंछी आयोग — 2007

- अध्यक्ष — न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी (पूर्व मुख्य न्यायाधीश)
- रिपोर्ट 2010 में — सात खंडों में।
- सरकारिया "सुधारवादी" है और पूंछी "आमूल परिवर्तनवादी"।
- "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" (during the pleasure of the President) वाक्यांश को हटाने की सिफारिश की।

- राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर ही हटाया जाना चाहिए।
- राज्यपाल की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की समिति;
- राज्यपाल का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल;
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश
- राज्यपाल को कुलाधिपति के पद से मुक्त करने का सुझाव

Venkatachaliah Commission - 2000	Punchhi Commission - 2007
○ National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC) ○ Justice M.N. Venkatachaliah (former Chief Justice of India) ○ It also gave recommendations on enforcement of Fundamental Duties, right to education, stricter anti-defection law, strengthening the Inter-State Council, and setting up a National Judicial Commission.	○ Chairman — Justice Madan Mohan Punchhi (former Chief Justice) ○ Report in 2010 — in seven volumes ○ Sarkaria is "reformist" while Punchhi is "radical". ○ Recommended removing the phrase "during the pleasure of the President"
○ Committee for appointment → Centre (Prime Minister, Home Minister), State (Chief Minister) and the Legislature (Speaker of Lok Sabha) ○ Term should be 5 years. ○ The Chief Minister should be consulted before removal ○ No interference in day-to-day functioning. ○ Discretionary powers should be exercised with restraint ○ The Governor should act as a friend, philosopher and guide.	○ The Governor should be removed only on a resolution of the State Legislature. ○ Committee for Governor's appointment: Prime Minister, Home Minister, Speaker of Lok Sabha and the concerned State's Chief Minister; ○ Governor's fixed 5-year term; ○ Clear guidelines for appointment of the Chief Minister ○ Suggestion to relieve the Governor of the office of Chancellor (of universities)

कसौटी	प्रथम ARC (1966)	राजमन्नार (1971)	सरकारिया (1988)	पूछी (2010)	वेंकट चलैया (2002)
मुख्यमंत्री से परामर्श	✓	✓	✓	—	✓
गैर-राजनीतिक	✓	—	✓	—	—
कार्यकाल की सुरक्षा	—	—	✓	✓	✓

कसौटी	निष्कर्ष (Takeaway)
1. मुख्यमंत्री से परामर्श	○ नियुक्ति या हटाने से पूर्व मुख्यमंत्री से "प्रभावी सलाह" अनिवार्य हो। ○ पाँच में से चार आयोगों ने यही कहा।
2. गैर-राजनीतिक	○ व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त हो, पर सक्रिय दलगत राजनीति से दूर हो।
3. कार्यकाल की सुरक्षा	○ 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल। "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" हटाने के बजाय कारण बताया जाए।

Criterion	First ARC (1966)	Rajamannar (1971)	Sarkaria (1988)	Punchhi (2010)	Venkatachaliah (2002)
Consultation with Chief Minister	✓	✓	✓	—	✓
Non-political	✓	—	✓	—	—
Security of tenure	—	—	✓	✓	✓

Criterion	Takeaway
1. Consultation with Chief Minister	○ "Effective consultation" with the Chief Minister must be mandatory before appointment or removal. ○ Four out of five commissions said the same.
2. Non-political	○ The person should be renowned in public life, but should be distanced from active party politics.
3. Security of tenure	○ A fixed 5-year term. Instead of removal "during the pleasure of the President," reasons should be given.

3) अध्यादेश शक्ति (अनुच्छेद 213)

- ❑ अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब :
 - ✓ विधानमंडल सत्र में न हो (जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, वहां दोनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हों)
 - ✓ राज्यपाल का यह **समाधान (Satisfaction)** हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके लिए **तत्काल कार्रवाई** करना आवश्यक है।
- ❑ स्वविवेकीय शक्ति नहीं → मंत्रिपरिषद् की सलाह
- ❑ राज्यपाल → किसी भी समय वापस ले सकता है
- ❑ 38वें संशोधन 1975 → "संतुष्टि" को न्यायिक समीक्षा से बाहर
- ❑ कृष्ण कुमार सिंह (2017) : न्यायिक समीक्षा के अधीन

❑ राज्य विधानमंडल के **पुनः समवेत (reassemble)** होने की तिथि से **6 सप्ताह** के भीतर इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए।

✓ अधिकतम जीवन → **6 माह + 6 सप्ताह**

✓ यदि द्विसदनीय राज्य विधानमंडल अलग-अलग तारीखों पर पुनः समवेत (reassemble) होते हैं, तो **छह सप्ताह की अवधि की गणना बाद वाली तारीख से की जाती है**

❑ निम्नलिखित 3 मामलों में राष्ट्रपति की निर्देश (अनुमति) :

- 1) राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति वाले विधेयक
- 2) राष्ट्रपति की राय के लिए रिज़र्व
- 3) कानून ऐसा, जो पास होने के बाद भी बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के अवैध माना जाएगा।

यदि राज्यपाल समवर्ती सूची के किसी ऐसे विषय पर अध्यादेश प्रख्यापित करना चाहता है, जो केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है, तो अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पूर्व निर्देशों की आवश्यकता होती है।

3) Ordinance Power (213)

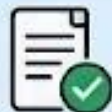
- ❑ An ordinance can be issued only when:
 - ✓ The state legislature is not in session (in states with a bicameral legislature, when either one or both Houses are not in session).
 - ✓ The Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.
 - ❑ **Not discretionary** → on ministers' advice
 - ❑ **Governor** → **can withdraw it at any time**
 - ❑ 38th Amdt. (1975): "satisfaction" not reviewable
 - ❑ K. K. Singh (2017): subject to judicial review
- ❑ It must be approved within **6 weeks of the State Legislature reassembling**.
 - ✓ **Maximum life** → **6 months + 6 weeks**
 - ✓ If the two Houses of a bicameral legislature reassemble on different dates, **the 6 weeks are counted from the later date**.
 - ❑ **President's instructions needed in 3 cases:**
 - 1) Bills that need the President's prior sanction
 - 2) Bills reserved for President's consideration
 - 3) Laws that would be invalid without the President's assent, even after being passed

If the Governor wishes to promulgate an ordinance on a subject in the Concurrent List that is repugnant to a Central law, the prior instructions of the President are mandatory.



अध्यादेश शक्ति : राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल



बिंदु	राष्ट्रपति	राज्यपाल
 कब	जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो	जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो
 संतुष्टि	तुरंत कार्रवाई आवश्यक	तुरंत कार्रवाई आवश्यक
 विषय-क्षेत्र	जिन पर संसद कानून बना सकती है	जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है
 प्रभाव व सीमा	संसद के अधिनियम के समान; वही सीमाएँ	राज्य अधिनियम के समान; वही सीमाएँ
 वापस लेना	किसी भी समय	किसी भी समय
 सलाह	मंत्रिपरिषद (PM) की सलाह पर	मंत्रिपरिषद (CM) की सलाह पर
 अनुमोदन	संसद पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह में	विधानमंडल पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह में
 किसी निर्देश की आवश्यकता	नहीं	हाँ — 3 मामलों में राष्ट्रपति का निर्देश आवश्यक



Ordinance Power: President vs Governor



Point	President	Governor
 When	When both Houses of Parliament or either House is not in session	When both Houses of the State Legislature or either House is not in session
 Satisfaction	Immediate action is necessary	Immediate action is necessary
 Legislative Domain	Matters on which Parliament can make laws	Matters on which the State Legislature can make laws
 Effect & Limits	Same as an Act of Parliament; subject to the same limitations	Same as a State Act; subject to the same limitations
 Withdrawal	At any time	At any time
 Advice	On the advice of the Council of Ministers (PM)	On the advice of the Council of Ministers (CM)
 Approval	Within 6 weeks of Parliament reassembling	Within 6 weeks of the Legislature reassembling
 Need for Instructions	No	Yes — in 3 cases, instructions from the President are required

भारतीय मुख्यमंत्रियों के रोचक रिकॉर्ड

भारत के मुख्यमंत्रियों से जुड़े 13 अनोखे तथ्य

1 सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री



पवन कुमार चामलिंग
(सिक्किम) — लगभग
24.5 वर्ष। दूसरे स्थान पर
नवीन पटनायक (ओडिशा)।

2 सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री



जगदंबिका पाल
(उत्तर प्रदेश) — 1 दिन,
और सतीश प्रसाद सिंह
(बिहार) — 5 दिन।

3 पहली महिला मुख्यमंत्री



सुचेता कुपलानी
(उत्तर प्रदेश, 1963)।

4 पहली दलित महिला मुख्यमंत्री



मायावती
(उत्तर प्रदेश, 1995)।

5 सबसे युवा मुख्यमंत्री



एम. ओ. हसन फारुक मरिक्कार
(पुडुचेरी, 29 वर्ष) और पूर्ण राज्य
में पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश,
37 वर्ष)।

6 दो अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री



नारायण दत्त तिवारी —
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
के मुख्यमंत्री।

7 युद्ध में शहीद होने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री



बलवंत राय मेहता
(गुजरात) — 1965 के
युद्ध के दौरान।

8 विदेश में जन्मे पहले अभिनेता-से-मुख्यमंत्री



एम. जी. रामचंद्रन —
श्रीलंका में जन्मे, बाद में
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने।

9 दुनिया की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री



ई. एम. एस. नंबूदरीपाद
(केरल, 1957)।

10 निर्दलीय विधायक होकर मुख्यमंत्री



मधु कोड़ा
(झारखंड, 2006)।

11 पद पर रहते हुए अयोग्य घोषित होने वाली पहली मुख्यमंत्री



जे. जयललिता
(तमिलनाडु, 2014)।

12 पद पर रहते हुए निधन वाले पहले मुख्यमंत्री



गोपीनाथ बोरदोलोई
(असम, 1950)।

13



मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति पद तक पहुंचे नेता

नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, और डॉ. शंकर दयाल शर्मा
(तत्कालीन भोपाल स्टेट)।

Interesting Records of Indian Chief Ministers

13 Unique Facts Related to India's Chief Ministers

1

Longest-Serving Chief Minister



Pawan Kumar Chamling (Sikkim) — about 24.5 years.
Second place: Naveen Patnaik (Odisha).

2

Shortest-Serving Chief Minister



Jagdambika Pal (Uttar Pradesh) — 1 day,
and Satish Prasad Singh (Bihar) — 5 days.

3

First Woman Chief Minister



Sucheta Kripalani
(Uttar Pradesh, 1963).

4

First Dalit Woman Chief Minister



Mayawati
(Uttar Pradesh, 1995).

5

Youngest Chief Minister



M. O. H. Farook Maricar (Puducherry, age 29);
among full-fledged states, Pema Khandu (Arunachal Pradesh, age 37).

6

Chief Minister of Two Different States



Narayan Dutt Tiwari —
Chief Minister of Uttar Pradesh and Uttarakhand.

7

Only Chief Minister Martyred in War



Balwantrai Mehta (Gujarat) — during
the 1965 war.

8

First Foreign-Born Actor to Become Chief Minister



M. G. Ramachandran —
born in Sri Lanka, later
became Chief Minister of Tamil Nadu.

9

Chief Minister of the World's First Democratically Elected Communist Government



E. M. S. Namboodiripad
(Kerala, 1957).

10

Independent MLA Who Became Chief Minister



Madhu Koda
(Jharkhand, 2006).

11

First Chief Minister Disqualified While in Office



J. Jayalalithaa
(Tamil Nadu, 2014).

12

First Chief Minister to Die While in Office



Gopinath Bordoloi
(Assam, 1950).

13

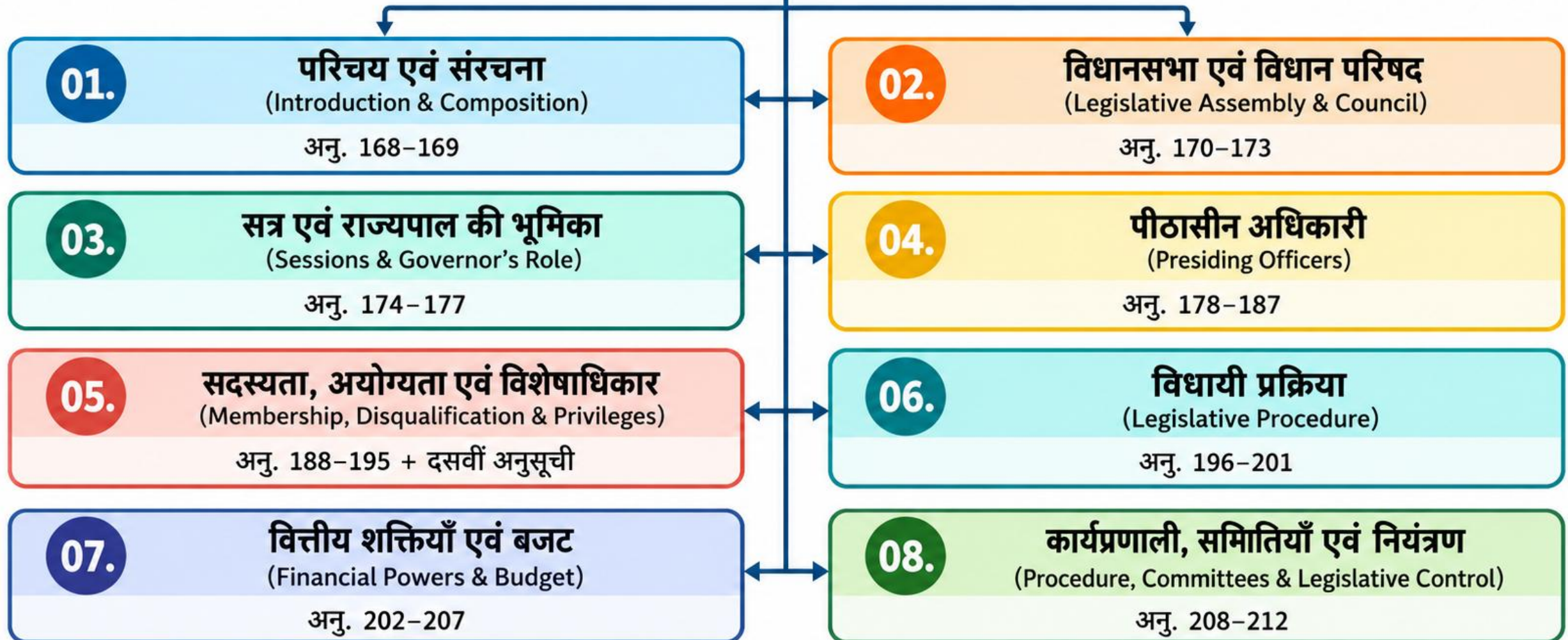


Leaders Who Rose from Chief Minister to President

Neelam Sanjiva Reddy, Giani Zail Singh, and Dr. Shankar Dayal Sharma (former Bhopal State).

अध्याय 21 : राज्य की विधायिका (State Legislature)

भाग VI → 168 से 212



Chapter 21: State Legislature

PART VI → 168 - 212

01. Introduction & Composition

(Articles 168 – 169)



02.

Legislative Assembly & Legislative Council

(Articles 170 – 173)



03. Sessions & Governor's Role

(Articles 174 – 177)



04.

Presiding Officers

(Articles 178 – 187)



05. Membership, Disqualification & Privileges

(Articles 188 – 195 + Tenth Schedule)



06.

Legislative Procedure

(Articles 196 – 201)



07. Financial Powers & Budget

(Articles 202 – 207)



08.

Procedure, Committees & Legislative Control

(Articles 208 – 212)



अनुच्छेद 168 → राज्यों में विधानमंडलों का गठन (Constitution of Legislatures in States)



क्र.	विधान परिषद	परिषद सदस्य	विधानसभा सदस्य
1	आंध्र प्रदेश	58	175
2	तेलंगाना	40	119
3	उत्तर प्रदेश	100	403
4	बिहार	75	243
5	महाराष्ट्र	78	288
6	कर्नाटक	75	224

- केवल 3 केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा — दिल्ली (70), पुडुचेरी (30), जम्मू-कश्मीर (90)
- 7वें संशोधन, 1956 द्वारा म.प्र. में विधान परिषद का प्रावधान किया गया, — राष्ट्रपति की अधिसूचना आज तक जारी नहीं हुई,
- तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010 पारित हुआ पर लागू नहीं हुआ — 2011 में विधानसभा ने परिषद उन्मूलन का प्रस्ताव पारित।

MLA (Member of
Legislative Assembly)

MLC (Member of
Legislative Council)

Article 168 → Constitution of Legislatures in States

Organs of the Legislature

Governor

Legislative Council → 6 States

Legislative Assembly → all 28 States

No.	State	MLCs	MLAs
1	Andhra Pradesh	58	175
2	Telangana	40	119
3	Uttar Pradesh	100	403
4	Bihar	75	243
5	Maharashtra	78	288
6	Karnataka	75	224

- Only **3 UTs** have an Assembly: **Delhi** (70), **Puducherry** (30), **J&K** (90)
- The **7th Amendment, 1956** provided for a Council in M.P., but the **President's notification was never issued**
- The **Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010** was passed but **never enforced**; in 2011 the Assembly voted to abolish the Council

*MLA (Member of
Legislative Assembly)*

*MLC (Member of
Legislative Council)*

अनुच्छेद 169 → विधान परिषदों के निर्माण और समाप्ति

- ❑ **शुरुआत (Initiative)** → विधान परिषद बनानी या समाप्त करना है, इसकी पहल स्वयं उस राज्य की **विधान सभा (Legislative Assembly)** ही कर सकती है।
 - ✓ राज्य विधानसभा को ऐसा प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करना होता है।
 - ✓ सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई
- ❑ **अंतिम शक्ति संसद के पास** → संसद कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का सृजन या समापन कर सकती है।
 - ✓ केवल साधारण बहुमत (Simple Majority)
 - ✓ संसद विधानसभा के संकल्प को मानने के लिए बाध्य नहीं
- ❑ अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा किया गया यह बदलाव, अनुच्छेद 368 के तहत 'संविधान संशोधन' नहीं माना जाता है।

1 शुरुआत (Initiative)

विधान परिषद बनानी या समाप्त करनी है, इसकी पहल स्वयं उस राज्य की **विधान सभा (Legislative Assembly)** ही कर सकती है।



2 राज्य विधानसभा में प्रस्ताव

राज्य विधानसभा को ऐसा प्रस्ताव **विशेष बहुमत** से पारित करना होता है।

विशेष बहुमत =

- सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत +
- उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई।

3 अंतिम शक्ति संसद के पास

संसद कानून बनाकर उस राज्य में **विधान परिषद का सृजन या समापन** कर सकती है।

संसद में यह कानून केवल **साधारण बहुमत (Simple Majority)** से पारित होता है।

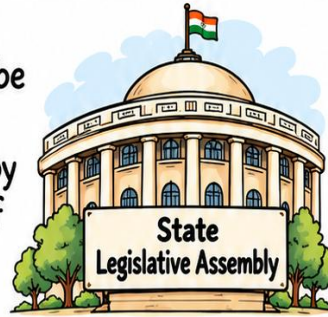


Article 169 → Creation and Abolition of Councils

- ❑ **Initiative** → only the **Legislative Assembly** of that State can start the creation or abolition of its Legislative Council
 - ✓ The State Assembly must pass the resolution by a **special majority**:
 - ✓ majority of total membership and at least two-thirds of the members present and voting
- ❑ **Final power lies with Parliament** → Parliament can create or abolish the Council in that State by law
 - ✓ Only a **simple majority** is needed
 - ✓ Parliament is **not bound** to act on the Assembly's resolution
- ❑ Such a law under Article 169 is **not deemed an amendment** of the Constitution under Article 368

1 Initiative

If a Legislative Council is to be created or abolished, the initiative can be taken only by the **Legislative Assembly** of that State.



2 Resolution in the State Legislative Assembly

The State Legislative Assembly must pass such a resolution by **Special Majority**.

Special Majority =

- Majority of the total membership of the House
- Not less than two-thirds of the members present and voting

3 Final Power Lies with Parliament

Parliament can create or abolish the Legislative Council in that State by making a law.

In Parliament, this law is passed only by **Simple Majority**.



Conclusion: The initiative is taken by the State Legislative Assembly, but the final decision is made by Parliament.

विधान परिषद : हाल की राज्य-स्तरीय पहलें

1 राजस्थान व असम



परिषद सृजन
के प्रस्ताव
पारित



- विधानसभाओं ने परिषद सृजन के प्रस्ताव पारित किए।
- संबंधित विधेयक 2013 से राज्यसभा में लंबित।



राज्यसभा में
लंबित

2 ओडिशा (2018) व पश्चिम बंगाल (जुलाई 2021)



परिषद सृजन
के प्रस्ताव
पारित



- विधानसभाओं ने परिषद सृजन के प्रस्ताव पारित किए।
- संसद में कार्यवाही लंबित।



कार्यवाही
लंबित

3 आंध्र प्रदेश

जनवरी 2020



विधानसभा ने परिषद उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया।



नवंबर 2021



यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया।



 **परिषद कायम।**



मुख्य बिंदु :

कुछ राज्यों ने परिषद के सृजन का प्रस्ताव पारित किया है, जबकि आंध्र प्रदेश में उन्मूलन का प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

Legislative Council: Recent State-Level Initiatives

1 Rajasthan & Assam

Resolution
for creation of
Legislative
Council



- The Legislative Assemblies passed resolutions for the creation of Legislative Councils.
- The related Bill has been pending in the Rajya Sabha since 2013.

Pending in
Rajya Sabha

2 Odisha (2018) & West Bengal (July 2021)

Resolution
for creation of
Legislative
Council



- The Legislative Assemblies passed resolutions for the creation of Legislative Councils.
- Action in Parliament is still pending.

Action
Pending

3 Andhra Pradesh

January 2020

The Assembly
passed a resolution
for the abolition of
the Legislative
Council.



November 2021

The resolution
was withdrawn.



Council Continues



Key Point

Some states passed resolutions for the creation of Legislative Councils, while Andhra Pradesh withdrew its proposal for abolition.

अनुच्छेद 170 → विधान सभाओं की संरचना (Composition of Legislative Assemblies)

- ❑ राज्य की विधान सभा
 - ✓ अधिकतम → 500 सदस्य
 - ✓ न्यूनतम → 60 सदस्य
- ❑ अपवाद :
 - ✓ सिक्किम (32)
 - ✓ मिजोरम (40)
 - ✓ गोवा (40)
- ❑ निर्वाचन की प्रकृति : प्रत्यक्ष चुनाव
 - ✓ सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों में से **एक** **सीट संघा** के लिए आरक्षित है।
- ❑ जनसंख्या का आधार : 1971 की जनगणना
- ❑ 170(2) → आवंटित सीट का अनुपात पूरे राज्य में लगभग एक समान हो।
- ❑ अनुच्छेद 170(3) → प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन
 - ✓ राज्य विधानसभा में कुल सीटों की संख्या → 1971 की जनगणना
 - ✓ निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन → 2001 की जनगणना
- ❑ संसद 'परिसीमन आयोग' (Delimitation Commission) का गठन
- ❑ अनुच्छेद 332 → अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण
- ❑ अनुच्छेद 333 → राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल-भारतीय का मनोनयन
 - ✓ 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त

उत्तर प्रदेश (403 सीटें)	पश्चिम बंगाल (294)	महाराष्ट्र (288)
गोवा (40)	मिजोरम (40)	सिक्किम (32)
जम्मू और कश्मीर (90)	दिल्ली (70)	पुडुचेरी (30)

Article 170 → Composition of Legislative Assemblies

- ❑ **State Legislative Assembly**
 - ✓ Maximum → **500 members**
 - ✓ Minimum → **60 members**
- ❑ **Exceptions:**
 - ✓ Sikkim (32)
 - ✓ Mizoram (40)
 - ✓ Goa (40)
- ❑ **Mode of election: Direct election**
 - ✓ Of Sikkim's 32 seats, one is reserved for the **Sangha**
- ❑ Art. 170(2) → seats allotted in the **same population ratio**
- ❑ Article 170(3) → **readjustment** after each Census
 - ✓ Total seats → **1971 Census**
 - ✓ Delimitation of constituencies → **2001 Census**
- ❑ **Delimitation Commission** set up by law of Parliament
- ❑ Article 332 → seats reserved for **SCs and STs**
- ❑ Article 333 → Governor nominated one **Anglo-Indian**
 - ✓ Discontinued by the **104th Amendment Act, 2019**

<i>Uttar Pradesh (403)</i>	<i>West Bengal (294)</i>	<i>Maharashtra (288)</i>
<i>Goa (40)</i>	<i>Mizoram (40)</i>	<i>Sikkim (32)</i>
<i>JK (90)</i>	<i>Delhi (70)</i>	<i>Puducherry (30)</i>

अनुच्छेद 171 → विधान परिषदों की संरचना (Composition of Legislative Councils)

- ❑ अधिकतम : विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई
- ❑ न्यूनतम सीमा : 40
- ❑ कुल सदस्यों का 5/6 हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि शेष 1/6 हिस्सा मनोनीत होता है:

- ❑ यह व्यवस्था अंतिम नहीं — संसद इसे बदल सकती है (अनु. 171(2));
- ❑ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और कुछ नामित
 - ✓ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (STV) द्वारा → गुप्त मतदान

अनुपात	किसके द्वारा चुने/मनोनीत जाते हैं?
1/3 सदस्य	इनका चुनाव राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों (जो संसद द्वारा निर्दिष्ट हों) के सदस्यों द्वारा
1/12 सदस्य	ऐसे शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। शर्त: ये संस्थान माध्यमिक स्तर (Secondary level) से नीचे के नहीं होने चाहिए।
1/12	ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक हों और उस राज्य में निवास कर रहे हों।
1/3 सदस्य	राज्य के विधायकों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं। (अर्थात् विधायक स्वयं को नहीं चुन सकते)।
1/6 सदस्य	171(5) → राज्यपाल द्वारा नामित – साहित्य, विज्ञान, कला (Art), समाज सेवा, सहकारी आंदोलन (Cooperative Movement)

Article 171 → Composition of Legislative Councils

- ❑ Maximum: **one-third** of the Assembly's total membership
- ❑ Minimum: **40** members
- ❑ **5/6** indirectly elected, **1/6** nominated:

- ❑ Parliament can change it by law (Art. 171(2))
- ❑ Partly **indirectly elected**, partly **nominated**
 - ✓ Elected by **proportional representation** (single transferable vote), by **secret ballot**

Share	Elected / nominated by
1/3	Members of municipalities, district boards and other local authorities specified by Parliament
1/12	Teachers with 3+ years' teaching in State institutions of at least secondary school level
1/12	Graduates of 3+ years' standing from any university in India, residing in the State
1/3	MLAs, from among persons who are not MLAs
1/6	Art. 171(5) → nominated by the Governor: literature, science, art, cooperative movement, social service

अनुच्छेद 172 → राज्य विधानमंडलों की अवधि

❑ अनुच्छेद 172 (1)

- ✓ सामान्य कार्यकाल : प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष
- ✓ समय से पूर्व विघटन : राज्यपाल
- ✓ राष्ट्रीय आपातकाल (352) के दौरान संसद विधि द्वारा कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक (कितनी भी बार) बढ़ा सकती है; परंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं।

❑ अनुच्छेद 172 (2)

- ✓ विधान परिषद स्थायी सदन है।
- ✓ यथाशक्य (As nearly as possible) एक-तिहाई (1/3) सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 → विधान परिषद {धारा 156}
और राज्यसभा {धारा 154} के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष

अनुच्छेद 173 → सदस्यों की योग्यताएं

- ❑ भारत का नागरिक
- ❑ निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ — नामांकन भरते समय एक उम्मीदवार के रूप में
- ❑ आयु:
 - ✓ विधानसभा — कम से कम 25 वर्ष;
 - ✓ विधान परिषद — कम से कम 30 वर्ष
- ❑ संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ।

अनुच्छेद 173 केवल 'सकारात्मक योग्यताओं' (Qualifications) की बात करता है (यानी सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए)। जबकि सदस्य को पद से हटाने या अयोग्य ठहराने वाली 'निर्हरताएं' (Disqualifications - जैसे लाभ का पद, मानसिक अस्वस्थता, दिवालियापन आदि) अनुच्छेद 191 में दी गई हैं।

Article 172 → Term of Legislatures

❑ Article 172(1)

- ✓ Normal term: **5 years** from its first meeting
- ✓ Earlier dissolution: by the **Governor**
- ✓ In a **National Emergency (Art. 352)**, Parliament may extend the term by law **one year at a time**, but not beyond **6 months** after the Emergency ends

❑ Article 172(2)

- ✓ The Legislative Council is a **permanent House**; it cannot be dissolved
- ✓ About **one-third** of its members retire every second year

RPA, 1951 → MLCs {Sec. 156} and Rajya Sabha members {Sec. 154} serve 6-year terms

Article 173 → Qualifications

- ❑ Must be a **citizen of India**
- ❑ Must take an **oath** before a person authorised by the Election Commission when filing nomination
- ❑ **Age:**
 - ✓ Legislative Assembly: at least **25 years**
 - ✓ Legislative Council: at least **30 years**
- ❑ Other qualifications prescribed by **Parliament**

Art. 173 sets out qualifications only. Disqualifications (office of profit, unsound mind, insolvency, etc.) are in Article 191.

अनुच्छेद 174 → सत्र (Sessions), सत्रावसान (Prorogation) और विघटन (Dissolution)

□ राज्यपाल

- ✓ सत्र बुलाना (Summoning the Sessions)
- ✓ सत्रावसान (Prorogue)
- ✓ विघटन (Dissolve)

□ समय सीमा (Maximum Gap) : 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं

- ✓ विधानमंडल के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

अनुच्छेद 175 और 176 → राज्यपाल का राज्य विधानमंडल में अभिभाषण (Address)

□ अनुच्छेद 175 : राज्यपाल का 'विशेष'

अभिभाषण : ऐच्छिक अनिवार्य

- ✓ दोनों सदनों को संबोधित
- ✓ राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं।

□ अनुच्छेद 176 : राज्यपाल का 'विशेष' अभिभाषण : अनिवार्य

- ✓ हर आम चुनाव के बाद नई विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में।
- ✓ प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र (आमतौर पर बजट सत्र) की शुरुआत में।

Article 174 → Sessions, Prorogation and Dissolution

❑ Governor

- ✓ Summons the House(s)
- ✓ Prorogues the House(s)
- ✓ Dissolves the Legislative Assembly

❑ Maximum gap: 6 months

- ✓ The gap between the last sitting of one session and the first sitting of the next must not exceed 6 months.

Articles 175 and 176 → Governor's Address to the Legislature

❑ Article 175: right to address (optional)

- ✓ Addresses either House or both Houses together
- ✓ May send messages to the House(s)

❑ Article 176: special address (mandatory)

- ✓ At the first session after each general election
- ✓ At the first session of each year (usually the Budget session)

अनुच्छेद 177 → मंत्रियों और महाधिवक्ता (Advocate-General) के अधिकार

- ❑ मंत्री तथा महाधिवक्ता (Advocate General) → दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार
- ❑ वे विधानमंडल की उस समिति की कार्यवाही में भी बोल सकते हैं और भाग ले सकते हैं, जिसके वे सदस्य नामित किए गए हों।
- ❑ मंत्री अपने सदन में मतदान कर सकता है, लेकिन महाधिवक्ता को विधानमंडल में मतदान का अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद 178 से 181 → विधान सभा के अधिकारी (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष)

- ❑ अनुच्छेद 178 → विधानसभा अपने दो सदस्यों को सभापति और उपसभापति के रूप में चुनेगी (choose)
- ❑ अनुच्छेद 179 (हटाना व त्यागपत्र) → तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (Effective Majority)
 - अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है।
- ❑ अनुच्छेद 180 (कार्यकारी अध्यक्ष) → जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य सदस्य यह कार्य करेगा।
- ❑ अनुच्छेद 181 (हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन) → : वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन (Preside) नहीं होंगे। वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और प्रथमतः वोट भी दे सकते हैं, लेकिन 'निर्णायक मत' (Casting vote) नहीं दे सकते।

Article 177 → Rights of Ministers and the Advocate-General

- ❑ **Ministers and the Advocate-General** → may speak in and take part in both Houses
- ❑ Also in any legislative committee they are named to
- ❑ Ministers vote in their own House; the Advocate-General has **no right to vote**

Articles 178–181 → Speaker and Deputy Speaker

- ❑ Article 178 → the Assembly **elects** its Speaker and Deputy Speaker from among its members
- ❑ Article 179 (removal and resignation) → removal by **effective majority**, after **14 days' notice**
 - The Speaker resigns to the Deputy Speaker, and the Deputy Speaker to the Speaker
- ❑ Article 180 (acting Speaker) → if the post is vacant, the Deputy Speaker acts; if both are vacant, a member appointed by the **Governor**
- ❑ Article 181 (removal resolution pending) → the Speaker **cannot preside**, but may speak and vote in the **first instance**; **no casting vote**

अनुच्छेद 182 से 185 → विधान परिषद के अधिकारी (सभापति और उपसभापति)

- ❑ अनुच्छेद 182 → विधान परिषद अपने दो सदस्यों को सभापति और उपसभापति के रूप में **चुनेगी (choose)**
 - ✓ परिषद की कार्यवाही में भाग लेने, बोलने और प्रथमतः (First instance) वोट का अधिकार होता है।
- ❑ अनुच्छेद 183 → रिक्त होना, त्यागपत्र देना, या हटाया जाना।
 - ✓ सभापति → त्यागपत्र → उपसभापति
 - ✓ उपसभापति → त्यागपत्र → सभापति
 - ✓ पद से हटाना → 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (Effective Majority) से
- ❑ अनुच्छेद 184 → जब सभापति का पद रिक्त हो, तो कर्तव्यों का पालन उपसभापति करेगा। यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हो, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य सदस्य यह कार्य करेगा।
- ❑ अनुच्छेद 185 → जब सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो अध्यक्षता नहीं करेंगे।
- ❑ **अनुच्छेद 186 → पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्तों**
 - ✓ राज्य विधानमंडल द्वारा कानून (विधि) बनाकर
 - ✓ राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) पर भारित (Charged) व्यय
- ❑ **अनुच्छेद 187 → राज्य विधानमंडल के सचिवालय**
 - ✓ प्रत्येक सदन) का अपना एक अलग सचिवालय
 - ✓ दोनों सदनों के लिए कुछ 'संयुक्त पदों' का सृजन
 - ✓ भर्ती और सेवा शर्तें : राज्य विधानमंडल
 - ✓ तब तक राज्यपाल → 'अध्यक्ष' और विधान परिषद के मामले में 'सभापति' के परामर्श से भर्ती और सेवा शर्तें नियम

Articles 182–185 → Council Chairman and Deputy

❑ Art. 182 → Council **chooses** a **Chairman** and a **Deputy**

Chairman

❑ Art. 183 → vacation, resignation and removal

- ✓ Chairman resigns to the Deputy Chairman
- ✓ Deputy Chairman resigns to the Chairman
- ✓ Removal: **effective majority**, after **14 days'** notice

❑ Art. 184 → if the post is vacant, the Deputy Chairman acts; if both are vacant, a member appointed by the

Governor

❑ Art. 185 → **Cannot preside** while a resolution for their removal is pending

- ✓ They may speak and vote in the **first instance**

❑ **Art. 186 → Salaries of presiding officers**

- ✓ Fixed by law of the State Legislature
- ✓ **Charged** on the State's Consolidated Fund

❑ **Art. 187 → Secretariat of the Legislature**

- ✓ Each House has its own secretariat
- ✓ Posts common to both Houses may be created
- ✓ Recruitment and service: regulated by the **State Legislature**
- ✓ Until then: rules by the **Governor**, after consulting the Speaker/Chairman